been informed by the hon. Member Shri Krishnacharya Joshi. That has not been done.

BEEDI AND CIGAR LABOUR BILL*

Shri A. K. Gopalan (Cannanore): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regulating employment and work in the factories manufacturing Beedi and Cigar in India.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for regulating employment and work in the factories manufacturing Beedi and Cigar in India."

The motion was adopted.

Shri A. K. Gopalan: I introduce the Bill.

ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (DECLARATION OF NATIONAL IMPORTANCE) AMENDMENT BILL

श्री बलवन्त सिंह मेहता (उदयपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष। राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम, १९५१ पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।

सभापति महोदय, सैंकड़ों और हजारों वर्षों की हमारी उपेक्षा और अंग्रेजों द्वारा की गयी, तोड़-फोड़ तथा वर्षा, आंधी, ओले और सर्दी गर्मी की मार के बाद भी हमारे सारे भारत वर्ष में आज भी सर्वत्र हजारों की संख्या में राष्ट्रीय महत्व के कई स्थान, अवशेष, स्मारक आदि मिलते हैं, जिनसे हमको अपने पुराने गौरव तथा संस्कृति की झलक मिलती है।

सबसे पहले सन् १९०४ में लार्ड कर्जन ने एंशेंट मानूमेंट्स प्रिजरवेशन ऐक्ट (प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम) का कानून बनाकर इन सब स्मारक, अवशेषों आदि को संरक्षण दिया तथा उनकी मरम्मत की व्यवस्था की। किन्तु जहां तक देशी राज्यों का सम्बन्ध था वह कानून उन पर लागू न हो सका और हमारी स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी अर्थात् रियासतों के विलीनीकरण के बाद भी सन् १९४८ तक इस कानून का उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब हमारा संविधान सन् १९५० में पास हुआ तब से हमारे केन्द्र के पुरातत्व विभाग का कार्यक्षेत्र संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और अवशेषों आदि तक सीमित हो गया। लेकिन जब सरकार ने देखा कि ऐसा होने पर भी 'ख' और 'ग' श्रेणी के राज्यों में बहुत से ऐसे स्मारक बाकी रह जाते हैं तो सन १९५१ में "एंशेंट एंड हिस्टारीकल मानूमेंट्स एंड आर्कियालाजीकल साइट्स एंड रिमेन्स (डिकलेरेशन आफ नेशनल इम्पार्टेंस ऐक्ट, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम) स्वीकृत किया गया। लेकिन उस वक्त भी जब वह कानून अमल में आया तो बहुत से लोगों को यह शिकायत रही कि उसमें भी बहुत से महत्वपूर्ण स्थान छूट गये हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि उस कानून को लाने के पहले कोई जांच पड़ताल नहीं हुई थी और न कोई सर्वेक्षण ही हुआ था।

दो वर्ष के बाद यह अनुभव किया गया कि कुछ स्थानों को और उसमें जोड़ने के लिये एक विधेयक लाया जाये, और डा० रघुवीर ने राज्य सभा में इसी सन् १९५१ के कानून के अन्तर्गत एक दूसरा संशोधक विधेयक पेश

---

*Published in the *Gazette of India Extraordinary* Part II—Section 2, dated 7-12-56, pp.....

[श्री बलवन्त सिंह मेहता]

किया और इस कमी की पूर्ति करानी चाही। सन् १९५४ में यह विधेयक राज्य-सभा के समक्ष रखा गया और जब उस पर बहस हो रही थी तब सरकार की ओर से कहा गया था कि एक बहुत बड़ा विधेयक सरकार की ओर से लाया जायेगा जिसमें बहुत से ऐसे स्थानों और अवशेषों आदि को शामिल कर लिया जायेगा जो कि छूट गये हैं।

लेकिन सभापति महोदय मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९५४ में यह विधेयक पेश किया गया था और आज सन् १९५६ में यह कानून पास हो रहा है और उस वक्त भी उस मूल कानून में ऐसी धाराएँ थीं जिनमें सन् १९०४ के अन्तर्गत जितने भी अवशिष्ट स्मारक स्थान आते थे और जो भारतवर्ष के महत्वपूर्ण स्थान में उनको राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने की बात थी। जब इसके ऊपर बहस हो रही थी तब उस वक्त हमारे यहां स्टेट् रिआरगेनाइज़ेशन (राज्य-पुनर्गठन विधेयक) बिल भी पेश हो रहा था और उसमें १२६वीं धारा के अनुसार यह सब बातें जोड़ने का उसमें उल्लेख था, इसलिये इसके मूल प्रस्तावक डा० रघुवीर को उन सब स्थानों को निकाल देना पड़ा और इस कारण उसका रूप बहुत ही संक्षिप्त रह गया है, सिर्फ इसमें दो, तीन ही विशेष स्थान हैं, दो नये स्थान हैं और एक पहले के कानून में है लेकिन उसकी अलग-अलग व्याख्या की गई है। ऐसा क्यों किया गया है और इसकी क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपके समक्ष प्रकाश डालना चाहता हूं।

हमारे भारतवर्ष में जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया हजारों की संख्या में ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण स्थान मिलते हैं और हमको उनसे अपनी पुरातन संस्कृति और इतिहास की प्रचुर समाग्री उपलब्ध होती है। आज वह हमारी पुरातन संस्कृति और इतिहास की सामग्री नष्ट होती जा रही है और वह खेद का विषय है कि अभी तक हमारी सरकार का उस ओर विशेष ध्यान नहीं गया है। यह राष्ट्र का धन और निधि नष्ट हो रही है। मैं आपको आगे चल कर उद्धरण दे कर बतलाऊंगा कि किस प्रकार आज उस राष्ट्रीय धन और निधि की क्षति हो रही है और यह दो, तीन मदें जो इसमें जोड़ी गई हैं अगर उनको जल्दी से सम्हाला नहीं गया तो हम राष्ट्र की बहुत बड़ी निधि को खो बैठेंगे और इसलिये इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि इनको जल्दी से जल्दी पास किया जाये।

इसके अलावा बहस के दौरान में यह भी कहा गया था कि नये विधेयक में जब कि वह आयेगा तब उसमें इनको रख दिया जायेगा लेकिन मैं समझता हूं कि अब इस हाउस (सभा) का काल बहुत कम रह गया है और कोई उम्मीद नहीं है कि इस सेशन (सत्र) में वह आ सकेगा और अगले सेशन में भी जो कि दो चार दिन का होने वाला है शायद ही आ सकेगा।

इसके अलावा जो स्टेट्स रिआरगेनाइजेशन ऐक्ट हमने पास किया है उसकी १२६वीं धारा के अन्तर्गत वे सब स्मारक आ जाते हैं लेकिन हमारे संविधान में जो सप्तम अनुसूची की ऐंटरीज (प्रविष्टियां) हैं उनमें संशोधन करना पड़ेगा और तभी उनसे कोई लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन उनमें संशोधन करने के बाद भी जब तक कि हम संविधान पास नहीं कर लेंगे तब तक बहुत मुश्किल है कि वह कानून का रूप धारण कर सकें इसलिये यह बहुत जरूरी समझा गया कि यह दो-चार मदें लेकर इस विधेयक में जोड़ी जायें

और जल्दी से जल्दी इसको कानून का रूप दे दिया जाय ।

इसमें जो खास-खास मदें हैं उनके ऊपर मैं थोड़ा सा इस समय प्रकाश डालना चाहूंगा । एक तो वह है जो पुराने कानून में पृष्ठ १४ पर "ऐनशिएट रुईस आफ बाडोली" (बाडोली के प्राचीन खंडहर) के सम्बन्ध में उल्लेख है । नये विधेयक में उसका विस्तार किया गया है और अलग-अलग उसका उल्लेख किया गया है और ऐसा क्यों किया गया है वह मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं । उसमें "ऐनशिएंटे रुईस" के नाम से उल्लेख किया गया है और कई मंदिर ऐसे बने हुए हैं और इतने सुंदर बने हैं कि भारतवर्ष में उनकी तुलना नहीं की जा सकती । जेम्स फर्गुसन की "ए हिस्ट्री आफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्चिटेक्चर" में इस बाडोली के मंदिर का उल्लेख आया है और उन्होंने लिखा है कि कुछ मंदिर अति सुन्दर हैं और उनकी टक्कर लेने वाले मंदिर अन्यत्र कहीं नहीं हैं । इसी तरह डा० ओझा जो कि हमारे इतिहास के बड़े मर्मज्ञ हैं उनका भी उद्धरण इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने रखूंगा । फर्गुसन साहब फरमाते हैं:

"Leaving these fragments, one of the oldest and certainly one of the most perfect, in Central India is the desecreated temple at Badoli, situated in a wild and remantic spot not far from the falls of the Chambal, whose distant roar in the still night is the only sound that breaks the silence of the solitude around them. The principal temple, represented in the woodcut No. 336 may probably, pending a more precise determination, be ascribed to the 9th or 10th century, and is one of the few of that age now known; it was originally dedicated to Siva. Its general outline is identical with that of the contemporary Orissan temples. But instead of the astylas enclosed porch or mandapa, it has a pillared portico of great elegance, whose roof reached half-way up the temple, and is sculptured with a richness and complexity of design almost unrivalled, even in those days of patient prodigality of labour".

इससे आपको अन्दाजा हो जायगा कि वे मंदिर कितने महत्वपूर्ण हैं । आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिरों तथा नागदा के "सास के मन्दिर" को छोड़ कर इन मंदिरों की समता करने वाले मंदिर भारतवर्ष में कोई नहीं हैं । भारतीय शिल्प के अद्वितीय ज्ञाता फर्गुसन ने यहां के मंदिरों की कारीगरी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । यह बड़े दुःख की बात है कि बाडोली मंदिर से विष्णु की शेषशैय्या मूर्ति गायब हो गई है हालांकि वह सारा का सारा प्रोटेक्टेड मौन्यूमेंट (संरक्षित स्मारक) है । मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि वह मौन्यूमेंट आपकी संरक्षत्ता में होते हुए भी वह मूर्ति कहां चली गई और वह क्यों नहीं वहां पर फिर से बैठायी जाती है । मालूम नहीं हमारा पुरातत्व विभाग सोता है जो उसका ध्यान इधर नहीं जाता . . . .

The Deputy Minister of Education (Dr. M. M. Das): Will the hon. Member tell me in some detail about this? The idol from which particular temple has been lost?

Shri Balwant Sinha Mehta: Sheshashayan. That idol has been removed from the ancient ruins of the Badoli temple. That is a protected monument.

Dr. M. M. Das: After independence or before independence?

Shri Balwant Sinha Mehta: Before independence.

Dr. M. M. Das: It was before independence.

श्री बलवन्त सिंह मेहता : वह विष्णु की मूर्ति वहां से गायब है । हमारा पुरातत्व विभाग न जाने क्या कर रहा है और वह सोता

[श्री बलवन्त सिंह मैहता]

है कि जागता है। लाखों रुपये हम बजट में इन ऐनशिएंट मौनयूमेंट्स को प्रीजर्व करने के लिये मंजूर करते हैं लेकिन यह बड़े खेद और दुर्भाग्य का विषय है कि वे हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और गौरवमयी अतीत के नमूने नष्ट होते जा रहे हैं।

इसी तरह उदयपुर का प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर जिस नागदा मंदिर के लिये श्री फर्गुसन ने लिखा है कि ऐसा सुन्दर मंदिर अन्यत्र देखने को नहीं मिलता वहां से भी कई चीजें गायब हो रही हैं और मुझे वहां के एक आदमी ने बताया कि एक कर्नल साहब वहां मोटर में बैठ कर गये और ऐनशिएंट मौन्यूमेंट को उठा कर ले गेये। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हमारा पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है।

इसी प्रकार से बहुत सी चीजें हैं जिनकी अभी सूची भी नहीं बनी है, सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। इसलिये मेरा सरकार से और पुरातत्व विभाग से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन जगहों की सूची बनाये। वह एक कमीशन (आयोग) बनाये जो सारे भारतवर्ष के अन्दर घूमे और सूची बना कर उनका माकूल इन्तजाम करे। जो चीजें आज आपकी संरक्षता में हैं वह भी खराब हो रही है तो मैं नहीं समझ पाता कि जो जगहें आपकी संरक्षता में नहीं हैं उनका क्या हाल होगा। यह बहुत आवश्यक है कि इन रुइन्स की अलग अलग व्याख्या की जाय। उनका समावेश पहले विधेयक में है, लेकिन मेरे विधेयक में उनकी व्याख्या की गई है। वह बहुत सुन्दर मन्दिर हैं, और मैं अपने दूसर भाइयों से भी अर्ज करूंगा कि वह भारतवर्ष की कला के बहुत उत्तम नमूने हैं। वहां की मूर्ति ८वीं ९वीं शताब्दी की बनी हुई है। जिस स्थान के बारे में मैंने अर्ज किया वह जहां पर चम्बल का बांध बन रहा है वहां पर एक फाल (झरना) है, जिसके लिये फर्गुसन ने भी लिखा है। उसके पास सड़क भी जाती है। यह भी चितौड़ जिले में है।

दूसरी चीज जो समावेश के लिये सुझाई गई है वह राक इंस्क्रिप्शन (शिला लेखों) के बारे में है। यह एक अजीब चीज है। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में ऐसी चट्टानें बहुत कम होंगी जिन पर हमारा इतिहास खुदा हुआ होगा। यह जो चट्टान है जिस पर इतिहास खुदा हुआ है, वह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। वहां पर दो शिलायें हैं। एक के ऊपर जैनियों का पूरा पूरा पुराण खुदा हुआ है, जिस का नाम उत्तम 'शिखर पुराण' है। उसकी प्रति नहीं मिलती है, सारे का सारा चट्टान पर खुदा हुआ है। उसका समावेश इस विधेयक में किया गया है। जो दूसरी चट्टान पर खुदा हुआ है। उसका समावेश इस विधेयक में किया गया है। जो दूसरी चट्टान है वह पार्श्वनाथ मन्दिर के हाते के अन्दर है। यह बिजौलिया के बिल्कुल पास है जो कि भीलवाड़ा जिले में एक छोटा सा कस्बा है। इतिहास के लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके संम्बन्ध में डा० ओझा ने जो कि इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान हैं, भी थोड़ा लिखा है और एपिग्राफिया इंडिया में भी इस के सम्बन्ध में उल्लेख है। उसको मैं थोड़ा सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।:

"The inscription is engraved on a flat undulating rock under a Mahuva tree, within the encircling wall towards the north of the big reservoir of water attached to the shrine of Parsvanath situated about ¼ mile to the south-east of the town of Bijolia. ..... The surface of the rock containing the inscription is not smooth but rough and undulating. The rock has suffered for centuries from exposures. Wherever the rock was originally defective, it has

been left blank; but now the portion of the rock used for engraving has also peeled off at places, and thus some of the important portions of the text have been totally destroyed."

यह पहले की बात है । उसमें भी यही कहा गया था कि इसकी क्षति हो रही है । अगर इस विधेयक में इसको नहीं लिया जाता तो उसकी क्षति की और ज्यादा सम्भावना है । इसकी हमारे इतिहास के लिये बहुत बड़ी देन है । हमारे हिन्दी साहित्य के आदि काल का ग्रंथ जो "पृथ्वीराज रासो" है उसके सम्बन्ध में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं । इस चट्टान के लेख से वे सब भ्रांतिया भी दूर हो जाती हैं । इस विषय में भी इसी एपिग्राफिया इंडिका से थोड़ा सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"'Prithviraj-Raso' of Chand Bardai is misleading and all but worthless. The fragment manuscript of *'Prithviraj—Vijaya'* discovered by Dr. Buhler in Kashmir is the contemporary work of poet Jayaratha. The order of chronology of the Chahamana princes as given in this poem also found support from the Harsha stone inscription of Chahamana Vigraharaj dated Vikram Samvat 1030 which mentions seven successive princes from Guvaka I to Vigraharaja II. But as the list supplied by this inscription was shorter than that given in the poem, some inscription of this period with a long list of these princes, exactly corresponding to that found in the poem, was a requisite so as to leave no room for suspicion. This desideratum has been supplied by the present rock inscription and therein lies its importance.

The chronology of the Imperial Chambana dynasty as given in the *'Prithviraj—Vijaya'* and as verified from the Bijholi rock inscription is, thus, to be accepted as authentic."

यह एक बहुत ही प्रमुख लेख मिला ह और इससे पृथ्वीराज के समय के इतिहास के ऊपर बहुत बड़ा प्रकाश पड़ता है । यह जो ग्रंथ है वह हमारे देश के इतिहास के लिये बहुत महत्वपूर्ण है । और आदि काल का माना जाता है । उसके नाम से कई लोग उसकी झूठी-झूठी प्रतियां निकाल कर राज्य सरकारों और भारत सरकार से सहायता ले रहीं हैं । यह शिलालेख इसके ऊपर भी काफी प्रकाश डालता है । इसलिये इस महत्वपूर्ण लेख को इस विधेयक में लिया गया । उसके पास ही जैसा मैंने अर्ज किया जो चट्टान है जिसके ऊपर एक पूरा ग्रंथ खुदा हुआ है, उसको पहले संरक्षण में ले लिया गया है, इसलिये इसको भी ले लिया जाये ।

इसके पश्चात् मैं मेनाल अथवा महानाल के सुप्रसिद्ध समारक के विषय में कहना चाहता हूं । ये १२ वीं शताब्दी का बना हुआ ह और चितौड़ जिले की बेगूं तहसील मे स्थित है । यह हमारे प्राचीन इतिहास की स्थापत्यकला का उत्कृष्ट नमूना है और हिन्दू भारत के इतिहास की एक सजीव कृति है । इसका संरक्षण होना भी बहुत आवश्यक ह । इस लिये इसको लिया गया है ।

यह जो तीनों चीजें ली गई हैं, मैं समझता हूं कि उनका बड़ा महत्व है और यदि इनको बहुत समय तक अरक्षित छोड़ दिया जायेगा तो बहुत सम्भव है कि यह बहुत खराब हो जाये । इसलिये मैं सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को स्वीकार करें और साथ ही जैसा मैंने निवेदन किया, पुरातत्व विभाग जो सोया हुआ सा है और लाखों रुपया खर्च करता है, वह भी थोड़ा सजग हो, और जो यह सब चीजें हमारे राष्ट्र की निधि हैं उनको बचावे । साथ ही जो हमारी बहुत सी मूर्तियां गायब हो गई हैं, उनको भी वहां फिरसे स्थापित करें । इसके लिये भी मेरी विनती

[श्री बलवन्त सिंह मेहता]

है कि जो अन्य चीजें हैं, जैसे राजस्थान का जन्तर मन्तर है, उसकी हालत भी अखबारों में निकली। मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार को उसको भी जल्दी से जल्दी लेना चाहिये। अभी हाल में कुतुब मीनार के वास्ते चार दिन पहले प्रश्न किया गया था। उसका हमारे मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा और सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया कि उसका एलक्ट्रिफिकेशन (विद्युतीकरण) हो रहा है या नहीं। मैं समझता हूं कि जो हमारे ऐसे ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थान हैं उनको जल्दी से जल्दी सरकारी संरक्षण में लेने के ऊपर विचार किया जाय।

Mr. Chairman: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

I have received chits from certain hon. Members who are desirous of speaking on this Bill. I will request them, in view of the fact that it is only an amending Bill, to kindly restrict their remarks to the particular monuments mentioned in this Bill and not to roam over the entire field and speak on general matters relating to any such declaration.

15 hrs.

Shri L. Jogeswar Singh (Inner Manipur): Mr. Chairman, I would confine my speech according to your advice. I am afraid the Bill is not an exhaustive one. It is a matter of an all India importance. Not only should it deal with one part of the country, but it should cover the whole of India. The original Bill of 1951 relating to the ancient and historical monuments and archaeological sites is also not exhaustive. It does not cover all the States in India. It covers only Hyderabad, Mysore, Travancore-Cochin and Rajasthan and many States have been left out, such as Saurashtra, groups of Eastern States in Orissa, Manipur, Tripura etc. The purpose of the Bill should be to include the historical monuments in the whole of India. But here a piece meal Bill has been placed before the House. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that though the amending Bill looks like being an all India Bill, is intended for Rajasthan only. I wonder why this piece-meal Bill has been brought before the House when many important monuments in many States of the country need be included in this Bill. I strongly suggest that the original Bill passed in 1951 should be amended in such a manner as to include all the States which I have just mentioned. This Bill is purely intended for Rajasthan but there are equally important ancient monuments in my State also. My State lies just on the border of Burma....

Mr. Chairman: I request the hon. Member kindly to restrict his comments in regard to the matters contained in clause 2 of this Bill. I already requested him to confine his remarks to that. I cannot allow him to refer to other monuments which are existing in another State, which have got no relation to this Bill. We are not on the general Bill now.

Shri L. Jogeswar Singh: I am only referring to the amendment of the original Bill of 1951.

Mr. Chairman: The present Bill seeks only to get declared certain monuments. If the hon. Member wants to speak about these monuments, he is perfectly entitled to do so, but if he wants to bring in cases of other monuments, I am afraid, I will not be able to allow it.

Shri L. Jogeswar Singh: I was only making some reference to the original Bill.....

Mr. Chairman: So far as the original Bill is concerned, it is sought to be amended by this Bill in respect of certain matters. The entire Bill is

not before us. I request the hon. Member kindly to speak on the Bill before us.

Shri L. Jogeswar Singh: I was only referring only to one or two things, so that they may be brought to the notice of the hon. Minister. My suggestion is that we should have a more exhaustive Bill of this nature....

Mr. Chairman: The hon. Member knows that before this Bill, there was another amending Bill by virtue of which the Central Government has been authorized to notify these other monuments in the other States also. The proper course for the hon. Member is that he should approach the Central Government and ask them to declare those monuments as of National Importance. In this Bill, I am sorry I cannot allow him to refer to any other monument existing in his State or elsewhere.

Shri L. Jogeswar Singh: I may mention that this Bill has been passed by the Rajya Sabha and at the present stage we can take it that it is more or less approved by Government. I would only request the hon. Minister to amend the original Bill of 1951 so as to include the monuments existing in other States also.....

Mr. Chairman: We are not concerned with other monuments existing anywhere. We are only concerned with the monuments which are mentioned here.

Shri L. Jogeswar Singh: My suggestion to the hon. Minister was that he might bring a similar Bill more comprehensive in nature in order to include the remaining monuments which are not included in the original Bill.

Mr. Chairman: So far as the monuments in his State are concerned, he may bring in a private Member's Bill.

Shri L. Jogeswar Singh: I was only saying that Government should take notice of it. That is all.

Shri Chattopadhyaya (Vijayavada): Mr. Chairman, I want to say a very few words in respect of this Bill. I congratulate the Government for including a number of monuments of historical and archaeological interest in the list and for their being protected and cared for. We all talk of historical and archaeological monuments, but we really do not realise to the fullest extent how very urgent it is to have these great treasure houses left to us by our ancestors preserved, every inch of it.

It is a great thing to see, for instance, the Fort of Chittoor which was very much neglected in the past, and now, I am sure, it is going to be resuscitated, renewed, revived and renovated. In other countries, we find that ancient monuments which went into oblivion have again been taken up, renovated and brought before the people of those countries, in order to inspire them on to greater consciousness and greater existence.

I think that with regard to this Bill, it is rather aggravating to have such an important subject dealt with piece-meal. My suggestion is that we have a Government notification in the gazette. Whenever the Government is moved to include a great historical or archaeological monument, instead of having this brought before Parliament every other day, it is better to have a notification in the gazette and inform the people that such and such a monument or such monuments have been included on the list.

I would like to congratulate the Government once more, and I do hope that when these monuments are renewed, when they are made important in the history of the life of our nation, they will inspire our artists, our painters to go and sit at the feet of our old Masters, who still live in the ruins, the ruins of our country, in the shape of these great monuments, which are far more healthy

[Shri Chattopadhyaya]

and whole than many of us who have lost our roots. I hope that these will become greater inspiring spots for the generations to come, and especially the younger generation, who have a bad habit of going out of India, without knowing anything of these great monuments, anything of the great traditions of this country, going out to learn artistic creation, going out to get inspiration from Europe and other places in the West—which is a very great national loss to us.

On behalf of the artists of this country, I should like to think the Government, indeed thank them for this great interest that they are showing in the monuments of this country, the great treasure houses of our culture, the great treasure houses of our consciousness, the great reminders of our ancestors who lived for us, who live by us and who are always there in order to make us go from the glory that was India to a greater glory that shall be India.

Dr. M. M. Das: At the begining I had no intention to inflict a long speech on the hon. Members so far as this particular motion is concerned because in the Upper House we, on behalf of the Government of India, have accepted this Bill, and in the Lower House also I thought that the only thing I could do was to submit to the Members of the House that Government accept this measure. But during the debate that has taken place on this measure, in the speeches of hon. Members that have spoken before me, several points have been raised, which, I think, in all fairness and justice to the Archaeological Department, should be explained.

So far as the present Bill is concerned, a few monuments of Rajasthan have been sought to be included into the list of monuments of national importance. The temples and monuments which are sought to be included in this list by this Bill are Parsvanath Jain Temple (Panchayatan) with the inscriptions of the 12th century and the Badoli Temple. The others are Menal (Mahanal) Temple, the Math and the ancient well and then the Suhaveshwar Temple and the Palace of Rani Suhavadevi. These are the monuments that are sought to be brought under the protection of the Government of India by this Bill, but I would like to remind my hon. friend that in Rajasthan there are many other important monuments which have not yet been included, for example—if I am to explain, I shall take some time; may I be permitted the time required?

Mr. Chairman: By all means he can go on.

Dr. M. M. Das: For example, I may point out that there are the temples of Osia in Jodhpur District and several other temples, the temples of Harihara, then the temple of Surya, the temple of Mahavira, the temple of Pipla Devi, the temple of Sachiyamata and others. They are all very important. All of them have very important inscriptions engraved on them. For instance, in the inscription engraved on the temple of Mahavira there is mention of the name of Vatsaraja of the Pratihara dynasty who flourished in about A.D. 770 to A.D. 800. Some of the temples were built in the eighth and ninth centuries A.D. These are all very important temples and they are situated in Rajasthan.

There are also others which deserve to be included in this list; for example, there is the Suriya Temple in Ranakpur in Pali District, and this temple is dedicated to the Surya and it contains fine sculptures. It is a fine specimen of mediaeval Hindu architecture. There is also the Ambikaji Temple of Jagat in Udaipur District which has excellent plastic decorations and is in a good state of preservation. Then there is the main

Jain Temple in the old city of Jawar famous for its silver mines. Then there is the Ghat with inscriptions at Nauchauki in Udaipur Town. The whole Ghat gives us an idea of the secular architecture of ancient times. The inscriptions on the Ghat not only furnish historical data but are themselves important as a poetical composition.

Shri Raghubir Sahai (Etah Distt.—North East cum Budaun Distt.—East): Is there any amendment on behalf of the Government that they should be included?

Dr. M. M. Das: I am coming to that because the question has been raised by hon. Members, and I want to take this opportunity to explain to the House the present position with regard to this particular Bill. My hon. friend need not be so impatient.

The legal position so far as the monuments of this country are concerned has changed perhaps two or three times. During the time of the Britishers, so far as the British administered provinces were concerned, archaeology was a Central subject. The British administered State Governments had nothing to do with the maintenance or protection of archaeological monuments. This continued till the time when we got our Independence. So far as the Native States were concerned, they had to make their own arrangements for maintenance and protection of archaeological monuments. With Independence, when these Native States were integrated into the Indian Dominion, all the archeological monuments situated in the Native States came responsible for the maintenance of all the archaeological monuments in the country. Then came our Constitution. Our Constitution-makers thought it wise to divide archaeology and ancient monuments of this country into two groups—one group containing those which are of national importance to be administered by the Central Archaeological Department, and the other group containing those which are of less importance to be administered by the State Governments. When the Constitution came into force, this was the legal position, and up till now this has been the legal position. The old monuments of India, archaeological, historical or whatever it might be, are divided into two groups, one covering those which are very important from the national point of view, which should be maintained and protected by the Central Archaeological Department, and the other covering those monuments of less importance, which should be maintained and protected by the State Governments.

After our new Constitution came into force in the year 1951, a Bill was brought before the House, the Bill which has been referred to by my hon. friend, the Mover of this motion, the Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Bill. During this time our officers of the Archaeological Department could not visit every important temple in the country, which is a vast country. In every corner of this country there are old, archaeological monuments and temples, and it was not possible for the few officers of our Archaeological Department to visit and take notice of all the important monuments, archaeological, artistic and otherwise, and bring them to the notice of the authorities. So, in the Bill that was passed in 1951, a schedule was attached giving the names of the important monuments of this country which should be maintained and protected by the Central Government. It can be imagined that this list was not a final list and it was defective. There were many temples which were not of sufficient importance to be included in this list, and there were others which were of sufficient importance to be included in this list but were

[Dr. M. M. Das]

left out of it. In February 1954, an amending Bill was brought forward by Government to rectify these errors. That Bill also was passed by both Houses, but even that Bill did not rectify all the errors. There are still some important temples to be visited, to be marked and to be taken notice of by our Archaeological Officers and then it should be decided whether they are so important as to be included in this list or not. This Bill was brought forward at the end of 1954. So far as this Bill is concerned, we have accepted it, not as the final amending Bill to the schedule, but because it also gives us some monuments which should be included in our schedule so far as Rajasthan is concerned.

Government have already prepared an amending Bill including all the important national monuments in the Schedule. In the meantime, the States reorganisation came and, as we have to give the name of the district, State, etc. where the monument is situated with the name of the State changing, the schedule had to be changed. That took some time and so we could not bring our final amending Bill before this House. We propose to do that in the very near future.

My hon. friend, Shri Chattopadhyaya, has made a very important suggestion, that for the inclusion of the name of an old and important monument in this list, it should not be necessary to come before the Parliament every time. It should be done by inserting a notice in the official Gazette. This has been made possible by the Seventh amendment of the Constitution; power has been given to be the Central Government to change or include in the schedule the name of important archaeological monuments by inserting a notice in the Gazette. But, we are to take that power from the House and in the proposed amending Bill most probably—I cannot commit—there will be a provision to this effect. I have explained the present position to the House.

My hon. friend mentioned about an idol that had been lost before the independence.

Shri Balwant Sinha Mehta: It was included in the schedule before the Independence but it was removed this year.

Dr. M. M. Das: I request him to give me the details in writing. It is a very serious charge brought against our department and it will be looked into. If from protected monuments important cultural pieces are lost, then some drastic step has to be taken. I assure this House that, if on an enquiry, we find that such a thing has happened, that some idols or cultural pieces had been lost, we shall take very drastic action.

He mentioned about the Jantar Mantar. Only today there was a question about Jantar Mantar. It belongs to the Rajasthan Government and formerly, most probably, it belonged to the Maharajha of Jaipur. The Rajasthan Government wanted to hand it over to the Government of India in 1950 but on one condition that the Government of India would run it as a living observatory. The Archaelogical Department has got no menas or machines for running the observatory and so we referred the matter to the Meteorlogical Department. It is a very great thing, no doubt but modern inventions have made our calculations very accurate and so that Department felt that no useful purpose would be served by running this observatory on ancient lines. We informed the Rajasthan Government accordingly. They informed us that they could hand over the monument to us provided some plots of lands within that area were handed over to the Rajasthan Government; they wanted to construct

some buildings. From the archaeological point of view, big buildings near such a monument destory the beauty and aesthetic quality of the monument. We wrote to them that we could hand over this piece of land provided when they constructed the building, they showed the plans and other things to the Director of Archaeology so that we could see whether it was going to destory the beauty, etc. of the moument. They have agreed in last October and we have taken steps to acquire the monument.

Then about Qutab Minar, only a few days back, I remember a question was put in this House by my hon. friend, Shri Pande, about the electrification. From what I could understand from the interpellations in this House, I feel that it is the desire of this House that it should be electrified. I am grateful to my hon. friend for giving me this opportunity to announce and to submit to the hon. Members that the Government had decided to implement the desire of the Members of this House and light the staircase to the top and to light the topmost balcony in the most attractive manner possible so that this minaret may attract the attention of people from a long distance. I think I have covered all the points and I accept this Bill.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur Distt. South): He has refered to a lot of monuments in Rajasthan, which are not covered by this Bill. Are there any amendments to include them?

Dr. M. M. Das: We are ourselves bringing a new Bill which will cover all of them—not only Rajasthan but other places too.

Mr. Chairman: Now, I shall put the motion....

Shri Subodh Hasda (Midnapore—Jhargram—Reserved—Sch. Tribes): On a point of information, may I know from the hon. Minister as to what has been done for the electrification of the Qutab Minar?

Dr. M. M. Das: It is going to be electrified and I said so.

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill further to amend the Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Chairman: There are no amendments and I shall put the clauses to the vote of the House.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री बलवन्त सिंह महता : मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि जब वह नया विधेयक लावेंगे, जो कि अपने आप में सम्पूर्ण होगा, उसमें राजस्थान के और भी कुछ स्मारक और पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान जोड़ दिये जायेंगे । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को जल्दी लावें ताकि चुनाव के बाद जो नया सदन बैठे उस समय उसके सामने सबसे पहला यही बिल हो क्योंकि यह हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे पुराने गौरव से सम्बन्धित है । अगर वह उसका काम अभी से शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं कि उस समय तक यह बिल ला सकेंगे ।

इसके साथ ही में डा० रघुबीर को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे आपके सामने इस विधेयक को लाने का मौका दिया । डा० रघुवीर अच्छे विद्वान हैं और यदि वह चाहते तो अपने ही प्रदेश के मानूमेंट्स का जिक्र

[श्री बलवन्तसिंह महता]

कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में जो चीज इतिहास की दृष्टि से और पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी उसको सामने रखा । उन्हीं स्थानों को लेकर वे इस विधेयक को लाये और मुझे आपके सामने उसे रखने का मौका दिया । इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं । साथ ही जो. . . .

Mr. Chairman: The hon. Member has not moved the motion. He is congratulating everybody. Will he kindly move the motion so that I may put it to the vote of the House?

श्री बलवन्त सिंह महता : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह बिल पास किया जाये ।

Mr. Chairman: Motion moved.

"That the Bill be passed."

श्री ब० द० पांडे : (जिला अलमोड़ा उत्तर पूर्व) : मैं इस विधेयक के तृतीय वाचन के समय कुछ थोड़े से शब्द कहना चाहता हूं :। यह जो विधेयक हमारे सामने है यह बहुत अच्छा है लेकिन यहां पर मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हमें ऐसे ही एनशिएट मौनयूमेंट्स को कायम रखना चाहिए जो कि हमारी पूर्व कीर्ति और गौरव के स्तम्भ हों और जिनसे हमें प्रेरणा मिलती हो अर्थात् जो सत्यं, शिवं सुन्दरम् हों, जिनके पीछे यश हो कीर्ति हो और प्रतिष्ठा हो । मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें जो कि बिलकुल टूटी हुई हैं और ईंटें मात्र रह गयी हैं और जो कि देखने में कुरूप लगते हैं ऐसे स्मारकों पर व्यर्थ में पैसा न खर्च किया जाना चाहिए । तुलसीदास के स्मारक और वृन्दावन के स्मारक और राजस्थान में चितौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तम्भ है वे हमारे अतीत गौरव की याद दिलाते हैं और हमारी पुरानी संस्कृति के उत्कृष्ट नमूने हैं और सरकार को अपने पुरातत्व विभाग द्वारा उनकी देखरेख कराते रहना चाहिए और उनको अच्छी हालत में बनाये रखना चाहिए । मैं चाहता हूं कि आप इन स्थानों को उसी तरह मेंटेन (संभाल) करें जैसे कि आप ताजमहल और कुतुबमीनार की करते हैं । लेकिन बेकार में कुरूप और बदसूरत चीजों को प्रीजर्व (रक्षित) मत करिये और उन पर व्यर्थ में रुपया न बर्बाद कीजिये । मैं कई स्मारक इस तरह के बेकार के बतला सकता हूं मैं चूंकि उस कोटी में नहीं हूं और मेरे पास वह लिस्ट नहीं है लेकिन मैं जानता हूं कि यहां दिल्ली में बहुत से ऐसे बेकार के स्मारक खड़े हैं और जो कि आंखों म कांटों के समान लगते हैं उनको तो तोड़ दिया जाना चाहिए । लाजपत नगर और विनयनगर के रास्ते में बहुत से इस तरह के बदसूरत खंडहर खड़े हैं जो कि बिलकुल बेकार हैं और उन पर रुपया खर्च करना बेकार है । मैं श्री चट्टोपाध्याय से पूर्णतः सहमत हूं कि ऐसे ही स्मारकों की देखरेख होनी चाहिए जो कि सुन्दर हों और जो कि हमारे प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति की याद दिलाते हों । मैं और अधिक न कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL

Shrimati Uma Nehru (Sitapur Distt. *cum* Kheri Distt.-West): Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Hindu Marriage Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Sir, this is a small and desirable amendment. I do not want to take much time of the House. This has already been passed by Rajya Sabha and I hope this House will also pass it.